NEERAJ®

Serving Education for Last 40 Years

# M.G.P.E. -13

# नागरिक समाज, राजनीतिक शासन तंत्र और संघर्ष

## ( Civil Society, Political Regimes and Conflicts )

**Chapter Wise Reference Book**
**Including Many Solved Sample Papers**

*Based on*

# I.G.N.O.U.

**& Various Central, State & Other Open Universities**

By: *Manish Kumar*

**NEERAJ PUBLICATIONS**
*(Publishers of Educational Books)*

Mob.: 8510009872, 8510009878 E-mail: info@neerajbooks.com
Website: www.neerajbooks.com

MRP ₹ 300/-

Content

# नागरिक समाज, राजनीतिक शासन तंत्र और संघर्ष

## ( Civil Society, Political Regimes and Conflicts )


Question Paper—June-2023 (Solved) ..... 1-2
Question Paper—December-2022 (Solved) ..... 1
Question Paper—Exam Held in March-2022 (Solved) ..... 1
Question Paper—Exam Held in August-2021 (Solved) ..... 1-2
Question Paper—Exam Held in February-2021 (Solved) ..... 1
Question Paper—December, 2019 (Solved) ..... 1-2
Question Paper—June, 2019 (Solved) ..... 1-2
Question Paper—December, 2018 (Solved) ..... 1-2
Question Paper—June, 2018 (Solved) ..... 1-2
Question Paper—December, 2017 (Solved) ..... 1-2
Question Paper—June, 2017 (Solved) ..... 1


| S.No. | Chapterwise Reference Book | Page |
|---|---|---|


1. नागरिक समाज की समझ ..... 1
( Understanding of Civil Society )

2. नागरिक समाज के तत्त्व ..... 12
( Elements of Civil Society )

3. नागरिक समाज : स्थानीय और वैश्विक ..... 22
( Civil Society : Local and Global )

4. गाँधी तथा स्वैच्छिकतावाद ..... 30
( Gandhi and Voluntarism )

5. राज्य और नागरिक समाज का मिलन-बिन्दु ..... 38
( Interface of Civil Society and State )

6. वैश्वीकृत बाजार में नागरिक समाज ..... 46
( Civil Society in Globalised Market )

7. नागरिक समाज और राजनीतिक शासन ..... 53
( Civil Society and Political Regimes )

8. नागरिक समाज, प्रतिरोध और विरोध ..... 61
( Civil Society, Resistance and Protest )

9. वैश्विक शान्ति आन्दोलन ..... 71
( Global Peace Movements )

10. शान्ति प्रक्रिया में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका ..... 81
( Role of NGOs in Peace Process )

11. शान्ति के लिए मानव अधिकार और संस्कृति ..... 91
( Human Rights and Culture for Peace )

12. भारत में शान्ति आन्दोलन ..... 101
( Peace Movements in India )

13. गाँधी, क्षमता निर्माण और सशक्तिकरण ..... 109
( Gandhi, Capacity Building and Empowerment )

14. आधारिक/जनपहल ..... 118
( Grassroots/People's Initiatives )

15. स्वैच्छिक कार्य का संगटन ..... 128
( Mobilising Voluntary Action )

16. वैश्विक शान्ति के लिए गाँधीवादी नागरिक समाज ..... 140
( Gandhian Civil Society for Global Peace )

# Sample Preview of the Solved Sample Question Papers

*Published by:*

NEERAJ PUBLICATIONS

www.neerajbooks.com

# QUESTION PAPER

***June – 2023***

*(Solved)*

## नागरिक समाज, राजनीतिक शासन तंत्र और संघर्ष

**( Civil Society, Political Regimes and Conflicts )** **M.G.P.E.-13**

*समय : 2 घण्टे ]* *[ अधिकतम अंक : 50*

***नोट :*** *कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक अनुभाग में से कम से कम दो प्रश्न चुनते हुए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।*

### भाग–I

**प्रश्न 1. नागरिक समाज के परंपरागत प्रारूप की चर्चा कीजिए।**

**उत्तर–संदर्भ–**देखें अध्याय-1, पृष्ठ-4, प्रश्न-1

**प्रश्न 2. गांधी के द्वारा सभी शक्तिशाली राज्यों की अस्वीकृति का क्या तर्क है?**

**उत्तर–संदर्भ–**देखें अध्याय-4, पृष्ठ-30, 'व्यक्ति की स्वायत्तता' तथा पृष्ठ-33, प्रश्न-1

**प्रश्न 3. आधुनिक राज्य के विभिन्न सिद्धान्तों का परीक्षण कीजिए।**

**उत्तर–संदर्भ–**देखें अध्याय-5, पृष्ठ-43, प्रश्न-3

**प्रश्न 4. हाल के कुछ अहिंसक आन्दोलनों पर एक आलेख लिखिए।**

**उत्तर**–यद्यपि भारत में अहिंसा का इतिहास अत्यंत प्राचीन है, परन्तु अहिंसात्मक आन्दोलन के इतिहास में महात्मा गाँधी अहिंसा के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रेरक व्यक्ति रहे हैं, इसलिए उन्हें विश्व में तथा विशेष रूप से भारत में अहिंसा का पुजारी कहा जाता है। देश में अहिंसा के विचार तो थे, परन्तु कार्यनीतियां नाममात्र की थीं, इसलिए गाँधीजी का आगमन अहिंसा के विचारों और कार्यनीतियों के विकास का जल-विभाजक (Watershed) कहा जाता है। गाँधीजी को अहिंसा के द्वारा कई उपलब्धियां प्राप्त होती दिखाई दे रही थी। जैसे–इससे भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में सहायता मिल सकती है, सामाजिक बुराइयों से समाज को मुक्ति मिल सकती है, दीर्घकालिक लक्ष्य प्राप्त करने की एक प्रभावकारी शक्ति के रूप में कार्य किया जा सकता है। गाँधीजी ने इनका विभिन्न कार्यों के लिए प्रयोग किया। विभिन्न कार्यों को अधिक धार्मिक और व्यावहारिक बनाने के लिए उन्होंने स्वयं को योग्य आयोजक, सुदृढ़ राजनीतिक रणनीतिकार और सामाजिक दूरदर्शक के रूप में प्रमाणित किया। उन्होंने अहिंसात्मक कार्यों के सिद्धान्त के रूप में सत्याग्रह का विस्तार किया। सत्याग्रह व्यक्तिगत न होकर विभिन्न राजनीतिक उद्देश्यों के लिए भी इसका प्रयोग किया जाने लगा। गाँधीजी के सत्याग्रह के लिए सत्य, आत्मपरिशुद्धता, रचनात्मक कार्यक्रम और शोषण तथा अन्याय का सक्रिय प्रतिरोध के प्रति प्रयास आदि आवश्यक थे। आधुनिक इतिहास में अहिंसात्मक आन्दोलन शस्त्राशस्त्र की लड़ाई के विकल्प के रूप में सार्वभौमिक और शक्तिशाली घटना है। विभिन्न प्रकार की राजनीतिक, सामाजिक प्रथाओं और विभिन्न प्रकार की सरकारों और उनके अधिकारों के प्रति अहिंसात्मक आन्दोलन उनका सामना करने के लिए अभूतपूर्व विकल्प है।

**गाँधी के बाद अहिंसात्मक आन्दोलन**–गाँधी के बाद अहिंसात्मक आन्दोलनों में कई परिवर्तन दिखाई देते हैं। वस्तुतः गाँधी के अहिंसात्मक सत्याग्रह के सिद्धान्तों का प्रभाव सम्पूर्ण विश्व पर पड़ा। गाँधी के विचारों का प्रयोग अहिंसात्मक आन्दोलनों ने अपने समाज, राजनीति और आर्थिक संरचनाओं में परिवर्तन लाने के लिए किया। अहिंसात्मक अभियान रणनीतियों और उनकी गतिशीलता से सम्बन्धित ज्ञान के विकास में विभिन्न नेटवर्किंग, मीडिया और विद्वानों के लेखों का योगदान रहा है।

**भारत में अहिंसात्मक आन्दोलन**–आजादी के पश्चात् भारत में विभिन्न प्रकार के सामाजिक-आर्थिक आन्दोलनों का कारण आचार्य विनोबा भावे थे, जिन्होंने सर्वोदय नेता के रूप में भूदान (भूमिदान) और ग्रामदान के अभियान का संचालन किया। भूदान आंदोलन गाँधी के जीवनकाल में संचालित हुआ था। तेलंगाना क्षेत्र में जब भूमि समानता के आधार पर साम्यवादियों ने हिंसा प्रारम्भ की, इसके विकल्प के रूप में सर्वोदय आन्दोलन शुरू किया गया। आजादी के पश्चात रचनात्मक कार्यकर्त्ताओं ने ग्रामीण असमानता को दूर करने के लिए भूमि पुनर्वितरण का कार्यक्रम चलाया। भूदान-ग्रामदान योजना के फलस्वरूप अहिंसात्मक आन्दोलन को बढ़ावा मिला। इन भूमि पुनर्वितरण कार्यक्रमों को राज्य और केन्द्र सरकारों ने भी अपनाया। भारत में सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अहिंसा पर आधारित अन्य आन्दोलन भी चलाये गये। उदाहरण के लिए, 1970 के दशक में जयप्रकाश

NEERAJ PUBLICATIONS www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com



नारायण ने सत्तासीन सरकार और आपात्काल घोषणा के विरुद्ध सम्पूर्ण क्रान्ति का आवाह्न किया। इसी प्रकार बांधों, विस्थापित लोगों के लिए, वन और अन्य प्रकार के प्राकृतिक संरक्षण के अहिंसात्मक आन्दोलन चलाये गये।

**विश्वव्यापी अहिंसात्मक आन्दोलन**–धीरे-धीरे भारत में फैले अहिंसात्मक आंदोलन देश के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार से पहुँच गये। इसका प्रतिरोध अभियानों के रूप में मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा 1950 और 1960 के दशकों में संचालित अमरीका नागरिक अधिकार आन्दोलन तथा 1950-1960 में नेल्सन मंडेला द्वारा दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति के रूप में दिखाई दिया। अधिनायकवादी और अर्धसत्तावादी शासन से लोकतांत्रिक शासन स्थापित करने के लिए अनेक देशों, अर्जेंटाइना, फिलिपाइन्स, चिली, पोलैंड, म्यांमार, चीन, पूर्वी जर्मनी, सर्बिया और जॉर्जिया आदि में अहिंसात्मक आन्दोलन की रणनीतियां अपनाई गईं। इस प्रकार राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के लिए तिब्बत, कोसोवे या पूर्वी तिमूर में आन्दोलन चलाये गये। अहिंसात्मक प्रतिरोध के सिद्धान्तों पर आधारित परमाणु विरोधी और शक्ति आंदोलन भी किये गये। पर्यावरण, मानव अधिकारों और आवश्यक भूमण्डलीकरण का संरक्षण भी गाँधीजी की अहिंसावादी नीतियों पर आधारित है।

**संदर्भ**–देखें अध्याय-8, पृष्ठ-69, प्रश्न-4

**प्रश्न 5. वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए।**

**उत्तर–संदर्भ**–देखें अध्याय-6, पृष्ठ-48, प्रश्न-1

**प्रश्न 6. गैर-सरकारी संगठन के विभिन्न वर्गीकरणों की व्याख्या कीजिए।**

**उत्तर–संदर्भ**–देखें अध्याय-10, पृष्ठ-82, 'कुछ प्रमुख गैर-सरकारी संगठन'

**प्रश्न 7. मानवाधिकारों को परिभाषित कीजिए। मानवाधिकार शिक्षा के महत्त्व पर प्रकाश डालिए।**

**उत्तर–संदर्भ**–देखें अध्याय-11, पृष्ठ-91, 'मानव अधिकार की परिभाषा', पृष्ठ-95, प्रश्न-1

**प्रश्न 8. वैश्वीकरण विरोधी आन्दोलन का समीक्षात्मक परीक्षण कीजिए।**

**उत्तर–संदर्भ**–देखें अध्याय-9, पृष्ठ-75, प्रश्न-1 तथा प्रश्न-2

**प्रश्न 9. विकेन्द्रीकरण की विशेषताएँ बताइए।**

**उत्तर–संदर्भ**–देखें अध्याय-14, पृष्ठ-124, प्रश्न-1, पृष्ठ-120, 'मानव विकास कार्यक्रमों में विकेंन्द्रीकृत सहयोग की विशेषताएँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विकेंद्रीकरण की विशेषताएँ'

**प्रश्न 10. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए–**

**(क) शांति शिक्षा**

**उत्तर–संदर्भ**–देखें अध्याय-12, पृष्ठ-103, 'शांति की शिक्षा'

**(ख) रचनात्मक कार्यक्रम**

**उत्तर–संदर्भ**–देखें अध्याय-4, पृष्ठ-32, 'रचनात्मक कार्यक्रम'

■■

NEERAJ PUBLICATIONS
www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

# Sample Preview of The Chapter

*Published by:*

NEERAJ PUBLICATIONS

www.neerajbooks.com

# नागरिक समाज
# (Civil Society)

## नागरिक समाज की समझ
## (Understanding of Civil Society)

1

### परिचय

नागरिक समाज की अवधारणा का उदय 1750 से 1850 के मध्य हुआ। प्रारंभ में नागरिक समाज को राज्य का ही पर्याय माना जाता था। परन्तु बाद में राज्य और नागरिक समाज को भिन्न-भिन्न अवधारणा माना गया। नागरिक समाज की अवधारणा का जन्म स्वेच्छाचारिता के उन्मूलन के उद्देश्य से हुआ। नागरिक समाज की अवधारणा सबसे पहले अरस्तू के राजनीतिक दर्शन में उल्लेखित शब्द Koinonia में देखने को मिलती है। अरस्तू नागरिक समाज को समान नागरिकों का नैतिक-राजनीतिक समुदाय मानता है। नागरिक समाज की अवधारणा को हम आधुनिक मान सकते हैं परन्तु इसका उल्लेख हमें प्राचीन राजनीतिक दर्शन में भी मिलता है। नागरिक समाज को 18वीं शताब्दी की लोक तान्त्रिक क्रान्ति का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा भी माना जाता है। विद्वानों ने भिन्न-भिन्न ढंग से नागरिक समाज को परिभाषित करने का प्रयास किया है इसी कारण नागरिक समाज पर एक सर्वमान्य परिभाषा का अभाव दिखता है।

प्रस्तुत अध्याय नागरिक समाज के विभिन्न पहलुओं से हमें अवगत कराता है। अध्याय में निम्नलिखित पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है—अरस्तु और नागरिक समाज की पारंपरिक धारणा, उत्तर-अरस्तू कालीन उद्विकास, नागरिक समाज की प्रारंभिक आधुनिक धारणा : फर्ग्युसन और स्कॉटिश प्रबोधन, नागरिक समाज और राज्य में विरोध : पैने, राज्य के प्राण तत्त्व के रूप में नागरिक समाज : टोकवील्ले तथा सार्वभौमिक राज्य और विशिष्ट नागरिक समाज : हीगल।

### अध्याय का विहंगावलोकन

#### अरस्तू और नागरिक समाज की पारंपरिक धारणा

अरस्तू ने अपने लेखन में koinonia शब्द का प्रयोग किया है, जिसमें समिति, समुदाय तथा समाज की अवधारणाएं शामिल हैं। रन सिमैन के अनुसार ''अरस्तू का मुख्य उद्देश्य पारिवारिक और राजनीतिक-सामाजिक परिस्थितियों के बीच अन्तर करना है''। अरस्तू द्वारा प्रस्तुत विभेदों की शृंखला राजनीतिक समाज तथा नागरिक समाज के मध्य के अन्तर को स्पष्ट करती है। अरस्तू के अनुसार प्राकृतिक समितियों में राज्य सबसे उच्च होता है। राज्य गृहस्थी से भिन्न होता है। गृहस्थी या परिवार से मिलकर एक गाँव बनता है तथा अनेक गाँव मिलकर नागरिक समाज का निर्माण करते हैं।

राज्य का निर्माण व्यक्ति के लिए होता है। राज्य की स्थापना समितियों या संघों (associations) के साध्य के रूप में होती है। राज्य का अस्तित्व स्वभाव से होता है। जो व्यक्ति राज्य की आवश्यकता महसूस नहीं करता वह मनुष्य नहीं हो सकता है। राज्य और परिवार (कुटुम्ब) एक समान नहीं होते हैं। राज्य-परिवार एवं व्यक्ति से पहले होता है। एक परिवार बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करता है जबकि एक राज्य व्यक्ति के अच्छे जीवन को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। किसी राज्य में जीवन की गुणवत्ता उस राज्य में रहने वाले लोगों एवं उनके लक्ष्यों पर निर्भर करती है। अरस्तू के अनुसार संविधान जीवन जीने का एक तरीका होता है, क्योंकि संविधान राज्य के नैतिक चरित्र को निर्धारित करता है। प्लेटो ने परिवार को राज्य में शामिल किया है, जिसकी अरस्तू ने आलोचना की है। अरस्तू परिवार एवं राज्य को भिन्न मानता है। परिवार

www.neerajbooks.com



(कुटुम्ब) में पति-पत्नी, स्वामी सेवक तथा पति-पत्नी और बच्चों के मध्य सम्बन्ध होते हैं। जबकि राज्य में शासक एवं शासित के मध्य समानता का सम्बन्ध होता है। इसी मत को जॉन लॉक (1632-1704) ने राजनीतिक निरंकुशतावाद की अपनी आलोचना में दोहराया है। राज्य को स्वतंत्र पुरुषों का स्थान माना गया है। अरस्तू के अनुसार polis उन स्वतंत्र पुरुषों का संघ होता है जो मित्रता एवं न्याय की दृष्टि से बँधे होते हैं।

## उत्तर-अरस्तू कालीन उद्‌विकास

अरस्तू का कहना है कि ''केवल गुणवत्ता के सिद्धान्त, संख्या की गुणवत्ता तथा जन-साधारण के दावों के तत्त्वों में सन्तुलन स्थापित करके ही राज्य को स्थिर किया जा सकता है तथा उसे क्रान्तियों की चपेट में आने से बचाया जा सकता है।'' अरस्तू मध्य वर्ग को समाजगत सन्तुलन के एक साधन के रूप में देखता है। अरस्तू मानता है कि मध्य वर्ग ही राज्यतंत्र है तथा यह समानता एवं सर्वसम्मति को पूरा करता है। मिश्रित संविधान के इस आदर्श को निम्नलिखित विद्वानों ने महत्त्व दिया है–पोलिबियस (263-120 ई. पू.), मार्कुस टुलियस सिसरो (106-43 ई.पू.), सेंट टॉमस अक्विनास (1224-74 ई.), निकोलो मौकियावेली (1527-1649 ई.) तथा ऐडम स्मिथ (1723-90 ई.)।

उत्तर-अरस्तू कालीन दौर में समबुद्धिवादियों ने विश्व नागरिकता की अवधारणा को प्रस्तुत किया। रोमन सम्राज्य ने समस्त मनुष्यों को इस अवधारणा के अन्तर्गत एकजुट करने का प्रयास किया। अरस्तू ने जिस एकता पर बल दिया था वह ईसाई धर्म के विकास से खण्डित हो गई। अरस्तू ने नागरिक सभा को चर्च से अलग कर दिया। अरस्तू ने दोहरी नागरिकता का भी सृजन किया। ईसाई धर्म सामाजिक एकता के लिए आत्मिक सहभागिता पर अधिक बल देता है। 'मनुष्य समूह' की परिभाषा अगस्टीन ने दी है। अगस्टीन की दृष्टि में रोमन गणतंत्र ईश्वर के प्रेम से बँधा हुआ एक समुदाय है। अक्विनास की रचनाओं में अरस्तू की धारणा पुनजीर्वित होती है क्योंकि इसमें राज्य को एक संगठन के रूप में देखा गया है। अक्विनास की दृष्टि में समुदाय तथा समाज एक-दूसरे के पर्याय हैं। आलीग्येरी दांते (1265-1321) ने एक सन्तुलित और पूर्ण द्वैतवाद को प्रस्तुत किया है। जिसमें राज्य एवं चर्च स्वतंत्र होकर भी एक-दूसरे के पूरक माने गये हैं। सामंती समाज में समाज रियासतों, समुदायों तथा संघों में विभाजित था परन्तु अब समुदाय तथा समाज की धारणाओं का उल्लेख राजनीतिक समाज के अन्तर्गत होता है।

## नागरिक समाज की प्रारंभिक आधुनिक धारणा : फर्ग्युसन और स्कॉटिश प्रबोधन

नागरिक समाज का उदय सामंती समाज के विघटन के साथ ही हुआ। राजनीतिक समाज तथा आध्यात्मिक समाज के मध्य अन्तर का मुद्दा तब उभरा जब ईसाई धर्म की एकता भंग हो गई, जिसका कारण प्रोटेस्टैंट मत का जन्म था। टॉमस हॉब्स (1588-1679) ने चर्च-केन्द्रित सत्ता को शिक्षण और प्रेरण माना है। हॉब्स के अनुसार केवल राज्य की क्रियाओं के द्वारा ही धार्मिक सिद्धान्तों को राजनीतिक दर्जा प्राप्त हो सकता है। लॉक के अनुसार राजनीतिक शासन पैतृक नहीं होता है। हॉब्स तथा लॉक दोनों ही विद्वान नागरिक समाज की विशिष्टताओं को वापस प्रकृति की स्थिति में ले जाने का प्रयास करते हैं।

**राजनीतिक और सामाजिक के बीच भेद का जन्म**–19 वीं शताब्दी के आरंभ में राज्य और समाज का एक और भेद हमारे सामने आया। नागरिक समाज अब अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं को अपने ही ढंग से पूरा करने के अधिकार का प्रयोग करता है। चार्ल्स-लूई एस. मॉन्टेस्क्यू (1689-1755) के अनुसार वाणिज्यवाद मनुष्यों को उनके पूर्वाग्रहों से मुक्त करता है। जो मनुष्य अपनी वास्तविक आवश्यकता को समझ लेता है वह मानवता के बोध को भी जान लेता है। यदि मनुष्य शान्तिपूर्ण व्यापार के आकर्षण को समझ ले तो उसे सैनिक अभियानों तथा युद्ध से नफरत हो जायेगी। वे राष्ट्रीय विविधता को समझने लगेंगे। वाणिज्य तो न्यायिक समाधान की भावना को लेकर आता है, जिससे हितों के बीच एक सन्तुलन स्थापित हो जाता है।

डेविड ह्यूम (1711-76) हित को व्यक्ति को समाज से जोड़ने वाला कारक मानता है। ऐडम स्मिथ ने सहयोग को समाज-निर्माण का आधार माना है। इस सन्दर्भ में स्वार्थ, संवेग तथा झगड़ों को भी ध्यान में रखना होगा। नागरिक समाज का गठन अनुबंध से भी होता है जिसके लिए न्याय एवं विश्वास की आवश्यकता होती है। स्कॉटिश प्रबोधन के चिन्तकों ने नागरिक समाज का एक नया वर्णन प्रस्तुत किया है। इन चिन्तकों ने नागरिक समाज की उस पारंपरिक अवधारणा को तोड़ने का प्रयास किया है जिसे सामाजिक अनुबंध चिन्तक मानते थे। इन चिन्तकों की दृष्टि में आर्थिक व्यवस्था अब नागरिक समाज का एक अहम हिस्सा बन गई है। यह विचार पडुआ के मार्सिलियस (1275-1342) की रचनाओं से लिया गया है। जिसके अनुसार भौतिक शान्ति से ही आर्थिक लाभों का आदान-प्रदान संभव होता है।

नागरिक समाज का विस्तृत विश्लेषण फर्ग्यूसन के ऐन ऐस्से ऑन दी हिस्ट्री ऑफ सिविल सोसायटी (1767) में प्रस्तुत किया गया है। फर्ग्यूसन ने राज्य और नागरिक समाज को एक समान माना है। नागरिक समाज एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जो कानून एवं सैनिक शक्ति के द्वारा कलाओं को, सांस्कृतिक उपलब्धियों को तथा जनभावना के बोध को निखारती है। फर्ग्यूसन कानून के विभाजन को जन-भावना को भ्रष्ट करने वाला मानता है। जन-भावना के ह्रास से स्वेच्छाचारी शासन का मार्ग प्रशस्त होता है। जब नागरिक समाज जन-भावना को नष्ट कर देता है तो इससे राज्य की शक्ति बढ़ती है। नागरिक समाज सैनिक शक्ति को भी स्थापित करता है। जिससे सैनिक शक्ति के बल पर सरकार बनाने के खतरे भी बढ़ जाते हैं।

www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com



भ्रष्टाचार के समाधान के लिए नागरिक समाज को एक सम्प्रभु केन्द्रीकृत संवैधानिक राज्य की आवश्यकता होती है। फर्ग्यूसन ने भी नागरिक समाज को मजबूत करने के लिए नागरिक समितियों को मजबूत करने का सुझाव दिया है। फर्ग्यूसन कहता है कि मनुष्य अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन सामाजिक समूहों में करते हैं। फर्ग्यूसन जन-भावनायुक्त संवैधानिक राजतंत्र को सर्वोत्तम मानता है। संवैधानिक राजतंत्र में मुख्य जोर नागरिक समाज और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों पर होता है।

## नागरिक समाज और राज्य में विरोध : पेने

नागरिक समाज के सन्दर्भ में दूरसंचरण की शुरुआत तब होती है जब 'राइट्स ऑफ मैन' में एडमंड बर्क (1729-97) के विचारों का पेने ने खण्डन किया। पेने ने नागरिक समाज के पक्ष में राज्य की शक्ति पर अंकुश लगाने की बात कही है। पेने राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है जबकि नागरिक समाज को एक अच्छाई। पेने के अनुसार नागरिक समाज जितना अधिक सक्षम होगा उतना ही वह अपने कार्यों पर नियंत्रण रख सकेगा। पेने यह मानता है कि अमेरिका के अलावा सभी जगह राज्य अपनी जनता के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। सरकारें जनता पर अधिक कर लगाकर समाज के भीतर वर्ग विभाजन को उत्पन्न कर देती है। पेने यह मानता है कि राज्य की शक्ति को कम करके नागरिक समाजों के एक अन्तर्राष्ट्रीय परिसंघ के गठन को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

पेने यह मानता है कि राज्य ही वैश्विक व्यवस्था तथा सद्भाव को संभव बनाते हैं। 'नागरिक समाज तथा साझा हितों पर विकसित होता है तथा सरकार द्वारा निर्मित कानूनों से सशक्त बनता है। व्यक्ति दूसरों के साथ सहज ही परस्पर व्यवहार करते हैं जो एक आत्मनिर्भर समाज के निर्माण में सहायक हैं।

पेने ने राज्य की ज्यादतियों का प्रतिरोध करने की आवश्यकता पर बल दिया है। पेने के अनुसार सहमति और अधिकार एक वैध राज्य को निर्देशित करते हैं। किसी भी राजनीतिक समूह तथा संस्था को यह निर्धारित करने का अधिकार नहीं है कि विश्व किसके द्वारा शासित होगा। क्योंकि जन्म से सभी व्यक्ति समान होते हैं तथा वे समान अधिकारों से सम्पन्न होते हैं। ये अधिकार व्यक्ति को ईश्वर द्वारा मिले होते हैं। राज्य की वैधता का आकलन हम नैसर्गिक अधिकारों से कर सकते हैं। इनका हस्तांतरण या विभाजन भी नहीं किया जा सकता है। पेने यह मानता है कि राज्य केवल तभी वैध एवं सभ्य होते हैं जब उनका गठन व्यक्तियों की सहमति से होता है। नागरिकों के प्रति सरकार के कर्त्तव्य होते हैं अधिकार नहीं। सरकार संविधान के अधीन होती है। संविधान में रहित सरकार उसी प्रकार है जिस प्रकार अधिकार से रहित सत्ता। संविधान का सरकार से वैसा ही सम्बन्ध होता है जैसा कानूनों का सम्बन्ध नयायिक अदालत से होता है। न्यायिक अदालत केवल कानूनों का पालन करती है। इसी प्रकार सरकार भी संविधान से ही शासित होती है।

## राज्य के प्राण तत्त्व के रूप में नागरिक समाज: टोकवील्ले

टोकवील्ले (1805-59) के अनुसार आधुनिक देशों के समक्ष एक समस्या स्वेच्छाचारी राज्य की है। जिसका समाधान नागरिक समाज के विकास से ही हो सकता है। लोकतान्त्रिक क्रान्ति की दृढ़ता के लिए नागरिक समितियों की अधिकता आवश्यक है। टोवील्ले के अनुसार नागरिक समितियाँ मुफ्त विद्यालय हैं, जिसमें नागरिक अपने अधिकारों एवं दायित्वों को सीखते हैं। टोकवील्ले की दृष्टि में नागरिक समितियाँ वे समितियाँ हैं जिनमें व्यक्ति अपना ध्यान अपने स्वार्थों तथा निजी लक्ष्यों से हटाकर सहयोग की दिशा में लगा सकते हैं। टोकवील्ले मानता है कि राज्य संस्थाएँ नागरिक समितियों में अस्तित्व और समन्वय को सुनिश्चित करती है। टोकवील्ले मानता है कि लोकतंत्र के विकास के लिए एक संगठित नागरिक समाज की अत्यंत आवश्यकता है जो राज्य से स्वतंत्र हो। टोकवील्ले ने तीन भाग वाला एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिसमें राजनीतिक समाज तथा राज्य के प्रशासनिक तंत्र का अन्तर स्पष्ट किया गया है।

## सार्वभौमिक राज्य और विशिष्ट नागरिक समाज : हीगल

हीगल ही वह विद्वान थे जिन्होंने राज्य और नागरिक समाज के मध्य अन्तर के बारे में विस्तृत रूप से लिखा। मैनफ्रेड रीडल के अनुसार ''नागरिक समाज के सम्बन्ध में हीगल की अवधारणा की तुलना बॉदैं की सम्प्रभुता की अवधारणा' तथा रूसों की जन-इच्छा (General will) की धारणा से की जा सकती है''। हीगल ने Biiregerliche Gesellschaft को राजनीतिक दर्शन की बुनियादी अवधारणा के साथ रखा जो बॉदैं की, मीलैनथन की, वुल्फ की तथा कांट की Biirger liche Gesllschaft परंपरा के अनुरूप ही है। हम यह कह सकते हैं कि हीगल से पहले आधुनिक अर्थ में नागरिक समाज की अवधारणा का अस्तित्व नहीं था।

परन्तु कीन ने इस विचार को स्वीकार नहीं किया। कीन के अनुसार 1750 से 1850 के मध्य अनेक अंग्रेज, फ्रांसीसी तथा जर्मन चिन्तकों का नागरिक समाज की अवधारणा से सरोकार था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जर्मन में कुछ ऐतिहासिक घटनाक्रमों ने नागरिक समाज की अवधारणा को प्रभावित किया। ये घटनायें थीं—एक सफल क्रान्ति का अभाव, राष्ट्र-राज्य का ढांचा देर से बनना, उपभोक्ता वस्तुओं का धीमा उत्पादन, संसदीय शासन की अशक्तता, राजनीतिक संस्कृति का कमजोर होना, इत्यादि।

हीगल ने राज्य और नागरिक समाज को भिन्न-भिन्न माना है। हीगल के अनुसार नागरिक समाज में ही निजी व्यक्तियों की सम्पूर्णता मूर्त रूप लेती है। नागरिक समाज को बुर्जुआ समाज माना गया है। जो निजी, स्वतंत्र एवं समान व्यक्तियों का समाज होता है। हीगल की दृष्टि में नागरिक समाज हितों का टकराव का प्रतिनिधित्व करता है। हीगल, नागरिक समाज को अपंग करने वाला समाज मानता है। हीगल नागरिक समाज को नैतिक जीवन का ऐतिहासिक रूप से उपजा क्षेत्र मानता है। जो परिवार एवं राज्य के बीच स्थित होता है। जिसमें बाजारी अर्थव्यवस्था, सामाजिक वर्ग, निगम तथा संस्थाएँ शामिल होती हैं। नागरिक समाज की उत्पत्ति आधुनिक विश्व की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है।

रूप में
वील्ले

www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com



हीगल के अनुसार बुर्जुआ समाज उन उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करता है जो मानव श्रम के यंत्रीकरण तथा विशेषीकरण के एक स्तर को आवश्यक बना देता है। हीगल कहता है कि नागरिक समाज के अन्दर समरसता की कोई संभावना नहीं होती है। यह समरसता केवल परिवार में ही पाई जा सकती है। नागरिक समाज में सम्बन्ध नाजुक होते हैं। नागरिक समाज में कभी-कभी टकराव के कारण अशान्ति भी उत्पन्न हो जाती है। हीगल ने नागरिक समाज में निम्नलिखित वर्गों की उपस्थिति स्वीकार की है—लोक सेवक, भूस्वामी, बुद्धिजीवी या विद्वान, वकील, डॉक्टर तथा पुरोहित। हीगल का विश्लेषण फर्ग्यूसन के ही समान है। हीगल ने कामगारों को बर्गर वर्ग में सम्मिलित किया है। यह वर्ग सामूहिक समितियों पर निर्भर करता है, यह वर्ग कम जन-भावना से युक्त होता है। हीगल फर्ग्यूसन और पेने के इस विचार से सहमत है कि आधुनिक नागरिक समाज लेन-देन करने वाले व्यक्तियों की एक जटिल व्यवस्था है परन्तु हीगल नागरिकता के सम्बन्ध में फर्ग्यूसन के विचारों को तथा नैसर्गिक सामाजिकता के सन्दर्भ में पेने के विचारों का खण्डन करता है। जो नागरिक समाज को एक अस्थिर क्षेत्र में परिवर्तित कर देते हैं इसलिए नागरिक समाज विशिष्टता से मुक्त नहीं हो पाते हैं। सामाजिक अन्यायों तथा असमानताओं को मिटाने के लिए राज्य उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। राज्य लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए भी नागरिक समाज में हस्तक्षेप कर सकता है।

कीन के अनुसार नागरिक समाज के सन्दर्भ में हीगल का विश्लेषण नागरिक समाज की अवधारणा के तीसरे चरण को प्रारंभ करता है। मार्क्स राज्य और नागरिक समाज के सम्बन्ध की आलोचना करता है। मार्क्स के अनुसार नागरिक समाज तो घोर भौतिकवाद की, संघर्ष की, सम्पत्तिगत सम्बन्धों की तथा अहंवाद की स्थली है। मार्क्स के अनुसार नागरिक समाज का जन्म मध्ययुगीन समाज के नष्ट हो जाने से हुआ है। मार्क्स के अनुसार मध्ययुग में नागरिक समाज जैसी किसी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि व्यक्ति कई समाजों (श्रेणी, रियासत) का हिस्सा था। इन समाजों के नष्ट हो जाने पर ही नागरिक समाज की उत्पत्ति हुई है। मार्क्स के अनुसार कानून मनुष्य की इच्छा से नहीं आता। आधुनिक राज्य के स्वरूप को नागरिक समाज की खण्डित प्रगति ही तय करती है।

ग्राम्स्की ने नागरिक समाज शब्द का प्रयोग मार्क्स से भिन्न ढंग से किया है। ग्राम्स्की के अनुसार यह संगठनों का क्षेत्र है जिसमें स्व-विनियमन तथा स्वतंत्रता की संभावना होती है। मार्क्स राज्य और नागरिक समाज को पृथक् मानता है परन्तु ग्राम्स्की ने दोनों को परस्पर सम्बन्धित माना है। स्कूल, चर्च, क्लब, पत्रिकाएँ तथा पार्टियाँ जैसी निजी संस्थाएँ नागरिक समाज के अन्तर्गत आती हैं। जबकि सरकार, अदालतें, पुलिस तथा सेना जैसी सार्वजनिक संस्थाएँ राजनीतिक समाज के अन्तर्गत आती हैं। नागरिक समाज की संस्थाएँ राजनीतिक एवं सामाजिक चेतना को सुदृढ़ करती हैं जबकि राजनीतिक समाज की संस्थाएँ वर्चस्व का माध्यम बनती हैं। बुद्धिजीवी वर्ग नागरिक समाज में ही प्रधानता कायम करता है। मार्क्स ने आर्थिक सम्बन्धों पर अधिक जोर दिया है जबकि ग्राम्स्की ने अधीरता पर। वर्चस्वशाली वर्ग की प्रधानता का परिपालन नागरिक समाज के द्वारा सांस्कृतिक रूप से होता है, परन्तु नागरिक समाज की यह प्रधानता सभी समाजों में एक समान नहीं पाई जाती है। सोवियत संघ की स्थिति के बारे में ग्राम्स्की लिखता है कि ''रूस में राज्य ही सब कुछ था, नागरिक समाज तो वहाँ आदिकालीन था। पश्चिम में राज्य और नागरिक समाज के मध्य मजबूत सम्बन्ध था इसलिए राज्य जब अस्थिर हुआ तो नागरिक समाज का मजबूत ढाँचा तुरन्त प्रकट हो गया।''

ओं डोनेल, कोल कोव्स्की, मलपनार, वाज़दा मिचनिक, हेबरमास, लिफोर्ट, टूरैन, बोबियो, बेफर्ट तथा कार्डोसो जैसे नव-मार्क्सवादी विद्वानों के विचारों में नागरिक समाज की अवधारणा पुनः प्रकट होती है। इन विचारों में एकदलीय शासन पद्धति की उत्पत्ति का पता लगाया गया है। हीगल ने नागरिक समाज और राज्य के बीच एकता की बात कही है परन्तु ऑगस्ट मारी फ्रांस्वा कॉम्टे (1798-1857) ने इसे स्वीकार नहीं किया है। कॉम्टे ने समाज शास्त्र को एक अलग विषय के रूप में स्थापित करने के प्रयास में हीगल की इस बात को खारिज कर दिया है। समाज शास्त्र ऐसा विषय है जो सामाजिक गतिकी तथा सामाजिक स्थैतिकी का विश्लेषण करता है।

## बोध-प्रश्न

**प्रश्न 1. नागरिक समाज की पारंपरिक धारणा को स्पष्ट कीजिए और किन कारणों से इसका विघटन हुआ।**

**उत्तर**—नागरिक समाज की पारंपरिक धारणा का विकास अरस्तू ने किया था। अरस्तू का काल लगभग 384 ई.पू. से 322 ई. पू. तक माना जाता है। अरस्तू ने अपने लेखन में जिस यूनानी दृष्टिकोण को व्यक्त किया है, उस दृष्टिकोण में कई बार koinonia शब्द का प्रयोग हुआ है। इस शब्द में कई प्रकार की धारणाएँ सम्मिलित थीं, जैसे—समिति, समुदाय तथा समाज की अवधारणाएँ। अरस्तू के लेखों में इन धारणाओं के लिए किसी अलग शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। रन सिमैन इस सन्दर्भ में कहता है कि ''अरस्तु का मुख्य उद्देश्य समाज और राज्य के बीच समानता स्थापित करना नहीं है, बल्कि अरस्तु का मुख्य उद्देश्य पारिवारिक एवं राजनीतिक-सामाजिक स्थितियों के बीच समानता स्थापित करना है।'' अरस्तू ने अपने लेखों में विभेदों की एक शृंखला प्रस्तुत की है जो राजनीति दर्शन के विकास से सम्बन्धित है। यह शृंखला राजनीतिक समाज तथा नागरिक समाज के मध्य अन्तर को स्पष्ट करती है। अरस्तू कहता है कि प्राकृतिक समितियाँ कई प्रकार की होती हैं तथा इनका निर्माण किसी अच्छे उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही किया जाता है और इन समितियों में सबसे उच्च स्थान राज्य का होता है। पुरुष तथा स्त्री मिलकर जो गृहस्थी बसाते हैं, राज्य उनसे अलग होता है। राज्य गृहस्थी से उच्च होता है। गृहस्थी का निर्माण स्त्री तथा

www.neerajbooks.com